वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2012-2013

मध्यप्रदेश शासन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2012—2013

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
भाग –एक		
	विभागीय संरचना	01
	अधीनस्थ कार्यालय	01
	विभाग के अधीन आने वाले उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	01
	विभाग के दायित्व	11
	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	11
	सामान्य या प्रमुख विशेषताएं	12
	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	12
भाग –दो		
	बजट विहंगावलोकन, बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय	13
भाग –तीन		
	राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	14
	वर्ष के दौरान विभाग की उपलब्धियॉ	19
भाग –चार		
	सामान्य प्रशासनिक विषय	21
भाग –पॉच		
	अभिनव योजना	21
भाग –छः		
	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	22
भाग –सात		
7.1	सारांश	22

मध्यप्रदेश शासन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2012–13

मंत्रालय

विभाग का नाम	–	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्री का नाम	–	श्री कैलाश विजयवर्गीय
सचिव का नाम	–	श्री हरिरंजन राव
उप सचिव का नाम	–	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव
अवर सचिव का नाम	–	श्री सुधीर कुमार कोचर

विभागाध्यक्ष

विभाग के अधीन कोई विभागाध्यक्ष नहीं है ।

भाग एक

1.1 – विभागीय संरचना

विभागीय संरचना एवं विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम/संस्थायें

मंत्री	
सचिव	
उप सचिव	
अवर सचिव	
अनुभाग अधिकारी	
निगम	संस्थायें
मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएसईडीसी)	मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (मैप–आईटी)

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में कोई विभागाध्यक्ष कार्यालय नहीं है। विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्य विभाग के अधीन मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (एम.पी.एस.ई.डी.सी.)/म.प्र. एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (मैप–आईटी) के माध्यम से संपन्न कराया जाता है।

1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण

विभाग के अधीन निम्नानुसार निगम/संस्था कार्यरत हैं :–

1.3.1 मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के त्वरित विकास एवं उन्नति हेतु उपयुक्त वातावरण बनाना इस संस्था का उद्देश्य है। निगम की कुल अधिकृत अंशपूंजी रू 3000.00 लाख है एवं प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 2191.25 लाख है। निगम को वर्ष 1992–93 के पश्चात राज्य शासन द्वारा कोई पूंजी प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान स्थिति में निगम का संचय एवं आधिक्य रूपये 175.34 लाख है। निगम के वर्ष 2010–11 के लेखे सांविधिक अंकेक्षण एवं महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षण के उपरान्त निगम की वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृत हो चुके हैं तथा विधानसभा पटल पर रखे जा चुके हैं। वर्ष 2011–12

का संवैधानिक अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है। लेखों पर कार्यालय प्रधान महालेखाकर ग्वालियर द्वारा अंकेक्षण पश्चात प्रमाण पत्र प्राप्त होना शेष है। शीघ्र ही इन लेखों को संचालकों के प्रतिवेदन के साथ संचालकों की सभा से स्वीकृत कराकर तथा वार्षिक साधारण सभा से लेखों को पारित कराकर इन्हें आगामी विधान सभा सत्र में पटल पर रखा जायेगा। मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड लि. की वित्तीय स्थिति प्रपत्र–क में अंकित है।

निगम द्वारा प्रवर्तित कम्पनियों में एम. पी. ऑन लाईन प्रमुख हैं। म.प्र. में इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं संवर्धन के लिए निर्दिष्ट एजेन्सी होने के कारण निगम अधोसरंचना संवर्धन एवं विकास की निम्नलिखित गतिविधियों में कार्यरत है :–

1.3.1.1 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 360 Points of Presence (POP) केन्द्रों की स्थापना की जाना है। परियोजना के अंतर्गत ब्लाक जिले से, जिले संभाग से तथा संभाग से भोपाल हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ जाएंगे। परियोजना के पॉच वर्ष तक संचालन हेतु उपयुक्त भागीदार मेसर्स ट्यूलिप आई.टी. सर्विस का चयन किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 360 Points of Presence (POP) केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। अब तक 332 पॉप केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। नेटवर्क आपरेटिंग सेन्टर क्रियाशील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 33 विभागों के लगभग 1300 कार्यालयों को Horizontal Connectivity प्रदान की जा चुकी है, जिनमें वाणिज्यिक कर विभाग, कोषालय, आबकारी कार्यालय, परिवहन विभाग, लोक सेवा केन्द्र, वन, नगर निगम भोपाल के 87 स्थान, उच्च न्यायालय एवं 50 जिला न्यायालय, ऊर्जा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व, महिला एवं बाल विकास तथा मछली पालन एवं मछुआ विकास प्रमुख हैं। लगभग 5,000 कार्यालयों को Horizontal Connectivity प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रगति पर है।

1.3.1.2 नागरिक सुविधा केन्द्र (Common Service Centre)

भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से प्रदेश में कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) की परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना की कुल लागत रूपये 14641.00 लाख रखी गई थी। लोक–निजी भागीदारी के माध्यम से संचालित इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी) द्वारा एक पारदर्शी निविदा

प्रक्रिया के माध्यम से भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार परियोजना के संभागवार संचालन हेतु निजी भागीदार संस्थाओं का चयन किया गया है। ये संस्थाऐं हैं :– AISECT (चंबल, सागर, होशंगाबाद, रीवा, तथा होशंगाबाद संभाग) CMS Computers (ग्वालियर एवं भोपाल संभाग), NICT (इन्दौर एवं उज्जैन संभाग), Reliance Communications (जबलपुर संभाग)। प्रदेश में 9232 नागरिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक लगभग 9299 सेन्टरों की स्थापना की जा चुकी है। इन सेन्टरों द्वारा खाद्यान्न उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन का कार्य भी सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

1.3.1.3 इलैक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एवं डेव्हलपमेंट सेंटर (ई.टी.डी.सी.)

निगम द्वारा इंदौर तथा भोपाल में केलीब्रेशन का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों जैसे गुना, मंडीदीप, पीथमपुर एवं देवास में केलीब्रेशन हेतु शिविरों का आयोजन किया गया है। निगम को केलीब्रेशन के इन्दौर जिसकी वैद्यता अप्रैल 2014 तक है एवं भोपाल स्थित लैब को **एनएबीएल प्रमाण** प्राप्त हुआ जिसकी वैधता 23.03.2013 तक है। एनएबीएल की वैधता 2 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है। भोपाल लैब के एनएबीएल के प्रमणीकरण की नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

1.3.1.4 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क – इन्दौर

निगम द्वारा वर्ष 1995–96 में इंदौर में स्थापित सॉफ्टेवयर टेक्नोलॉजी पार्क अब पूर्ण रूप से कार्यशील हो चुका है। इस पार्क का लगभग 80,000 वर्गफुट क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है। इस पार्क में मेसर्स कम्प्यूटर साईन्स कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि. जो कि साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख **फॉर्चून–500** कम्पनी है एवं कम्प्यूटर साईन्स कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी है, द्वारा अपनी इकाई 61,000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित की गई है। इससे निगम को रू 1.91 करोड़ प्रतिवर्ष की आय प्राप्त हो रही हैं।

1.3.1.5 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एसईज़ेड) – भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर।

ग्वालियर, सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाकर संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर में राज्य शासन द्वारा आवंटित भूमियों पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भोपाल में आई0 टी0 पार्क की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम बड़वई, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समीप 212 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस भूमि पर अधोसंरचना विकास का कार्य म.प्र. गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मंडल के माध्यम से शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है।

चित्र– सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ग्वालियर

1.3.1.6 (ए) मंत्रालय में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

मंत्रालय में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निगम द्वारा मंत्रालय में अति अत्याधुनिक संसाधनों एवं अधोसंरचनाओं सहित कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र में मार्च 2005 से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है। निगम द्वारा अभी तक लगभग 3000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। निगम इस प्रशिक्षण केन्द्र में उच्च तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ करने के लिए प्रयासरत् है।

चित्र– मंत्रालय स्थित कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

1.3.1.6 (ब) 1.3.16 स्किल गैप प्रशिक्षण केन्द्र, महू (इन्दौर)

मध्य प्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा महू (इन्दौर) में ट्रेनिंग सेन्टर के लिए 15,000 वर्गफिट की भूमि पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लि. द्वारा सबलेटिंग पर उपलब्ध कराने हेतु आरक्षित की गई है। इस ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण कार्य पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लि. द्वारा किया गया है। इस केन्द्र को जनभागीदारी योजना के तहत संचालित किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु आईप्राईमेड एज्युकेशन सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड को कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं।

1.3.1.7 स्टेट पोर्टल एवं स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे (SSDG)

राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना के अंतर्गत नागरिकों को दूरस्थ अंचलों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से त्वरित, पारदर्शी एवं सुविधाजनक रूप से सेवाऐं प्रदान करने के उद्धेश्य से भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से स्टेट पोर्टल एवं स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे (SSDG) की स्थापना की जा रही है। यह मूलतः आई.टी. अधोसंरचना के रूप में स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे की स्थापना एवं स्टेट पोर्टल के निर्माण से संबंधित मिशन मोड परियोजना है। परियोजना पीपीपी मोड पर संचालित की जा रही है जिसके लिए टीसीएस का चयन निजी भागीदार के रूप में किया गया है। टीसीएस के द्वारा परियोजना के वास्तविक संचालन प्रारम्भ से आगामी 3 वर्ष तक सपोर्ट प्रदान किया जायेगा। परियोजना की कुल लागत 10.84 करोड़ रूपये है जो भारत

सरकार द्वारा वहन की जा रही है। प्रारम्भिक चरण में 6 विभागों की 41 सेवाऐं SSDG पोर्टल पर उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजनांतर्गत 13 विभागों की वेबसाईट्स का पुर्ननिर्माण भारत सरकार की वेब गाईडलाईन्स के अनुरूप किया जा रहा है।

1.3.1.8 *स्टेट डाटा सेन्टर*

भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना की गई है। उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए रू 55.75 करोड़ का अनुमोदन किया था। जिसमें रू 18.37 करोड़ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अंश एवं रू 37.38 करोड़ की राशि राज्यांश के रूप में स्वीकृत की थी है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय सहायता रू 4.19 करोड़ एवं भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की स्वीकृत राशि रू 37.38 करोड़ की 20% राशि रू 7.48 करोड़ निगम को प्राप्त हो चुकी है।

इस सेन्टर में शासन के विभिन्न विभागों का डाटा सुरक्षित रूप से रखा एवं उपयोग किया जा सकेगा। नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के तहत प्रस्तावित स्टेट डाटा सेन्टर राज्य सरकार की सेवाओं को संघटित करने, दक्ष जी–टू–जी, जी–टू–सी एवं जी–टू–बी इलैक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदान करने के लिए अधोसंरचना को जुटायेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। निगम द्वारा स्टेट डाटा सेन्टर के क्रियान्वयन हेतु मेसर्स एच. सी. एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर को कार्यादेश दिया जा चुका है। स्टेट डाटा सेन्टर का कार्य पूर्ण होकर इसका संचालन दिनांक 12.12.2012 से प्रारंभ हो चुका है।

चित्र– स्टेट डाटा सेन्टर, भोपाल

1.3.1.9 टेलीसमाधान केन्द्र (कॉल सेन्टर) की स्थापना

निगम द्वारा आम नागरिकों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने एवं उनकी शिकायतें दर्ज करने हेतु एक अत्याधुनिक कॉल सेन्टर की स्थापना वर्ष 2008 में की गई है। कॉल सेन्टर पर स्कूल शिक्षा, राजस्व, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन, पर्यटन, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, गृह विभाग सहित 21 विभागों/संस्थाओं की 325 सेवायें उपलब्ध है। प्रदेश का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 155343 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है एवं योजनाओं/कार्यक्रमों की आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है। अभी तक नागरिकों से 34.10 लाख से अधिक कॉल्स प्राप्त हुए हैं जिनमें से 95 प्रतिशत कॉल्स का निराकरण किया जा चुका है।

1.3.1.10 अन्य गतिविधियॉं

निगम द्वारा शासन के विभिन्न विभागों के लिए इलैक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने व कम्प्यूटराईजेशन आदि कार्यों के लिए परामर्श सेवाऐं प्रदान करने जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। निगम द्वारा वर्तमान वर्ष में इलैक्ट्रॉनिक सामग्री जैसे कम्प्यूटर एवं आई.टी. सॉल्यूशन्स (नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर आदि) शासन के विभिन्न विभागों को प्रत्यक्षतः उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। निगम द्वारा शासन के निर्देशानुसार विभिन्न सेमीनारों/प्रदर्शनियों जैसे आई.टी. बिज़ बैंगलोर आदि में भाग लिया गया एवं इनका आयोजन किया गया है।

1.3.1.11 निगम द्वारा प्रवर्तित कम्पनियों का कार्य निष्पादन

(i) फुजुत्सु ऑप्टेल लिमिटेड (फोटेल)

कम्पनी का परिसमापन वर्ष 2011–12 में हो चुका है।

(ii) एमपी ऑन लाईन :–

राज्य शासन द्वारा सुदूर क्षेत्रों में नागरिकों को कहीं भी कभी भी (Any Time-Anywhere) शासकीय सेवाऐं प्रदान करने के लिए स्थापित एमपीऑनलाईन मध्यप्रदेश शासन एवं टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेस का संयुक्त उपक्रम है जिसमें मध्यप्रदेश

शासन की एम.पी.एस.ई.डी.सी. के माध्यम से 11 प्रतिशत की भागीदारी है। एमपीऑनलाईन द्वारा मुख्यतः शैक्षणिक, भर्ती संबंधी, बी–टू–सी एवं काउंसिलिंग संबंधी लगभग 175 सेवाऐं लगभग 3000 एमपीऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। पटवारी परीक्षा के ऑनलाईन आयोजन के लिए एमपीऑनलाईन को वर्ष 2012 का प्रतिष्ठित मंथन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एमपीऑनलाईन देश के सर्वाधिक सफल लोक सेवा प्रदाय मॉडलों में से एक है।

1.3.2 मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (MAP_IT)

इस संस्था का गठन वर्ष 1999 में किया गया। यह संस्था मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह राज्य शासन की पंजीकृत सोसायटी है जो राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिये कार्य करती है।

1.3.2.1 मैप आई.टी. के उद्देश्य :–

- राज्य सरकार के विभागों/एजेन्सियों को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परामर्श देना तथा उन्हें कम्प्युटरीकरण और नेटवर्किंग के कार्यो में सहायता प्रदान करना।
- उद्योग तथा निवेशकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित कर सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा देना।

संस्था मान. मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित शासी निकाय के नियंत्रण में कार्य करती है तथा माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। वित्त विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग इस शासी निकाय के सदस्य हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप–आई.टी. इस सोसायटी के शासी निकाय के सदस्य सचिव हैं। इस संस्था को राज्य शासन की ओर से दिये गये अनुदान प्रपत्र–ख में उल्लेखित है।

1.3.2.2 लेखा परीक्षणों की स्थिति –

मैप आई.टी. के वर्ष 2009–10 एवं 2010–2011 के लेखों का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है।

1.3.2.3 मैप आई.टी. की उपलब्धियाँ

(i) नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान –

भारत सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण परियोजना प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य शासकीय कार्यो में ई–गवर्नेन्स के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेशनल ई–गव्हर्नेंस प्लान के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा मैप–आई.टी. को नोडल एजेन्सी बनाया गया है।

(ii) स्टेट ई–गव्हर्नेन्स मिशन मोड दल के विकास के लिए तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति :

नेशनल ई–गव्हर्नेन्स प्लान के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा मैप–आई.टी. को नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के सहयोग से ई–गव्हर्नेन्स परियोजना के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में स्टेट ई–मिशन टीम का गठन किया गया है।

(iii) ई–डिस्ट्रिक्ट

आम नागरिकों को कियोस्क के माध्यम से त्वरित, पारदर्शी एवं सुविधाजनक लोक सेवाऐं प्रदान करने के लिए यह परियोजना मध्यप्रदेश में सर्व प्रथम इन्दौर, सागर, ग्वालियर, गुना एवं शिवपुरी जिलों में पायलट आधार पर प्रारम्भ की गई थी। 27 जुलाई, 2012 को पायलट का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है। इसके फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा प्रदेश के शेष 45 जिलों के लिए रूपये 115.00 करोड़ की लागत से यह परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसका क्रियान्वयन लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(iv) ई–टेंडरिंग

सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन के विभिन्न विभागों/एजेन्सियों के निविदा संबंधी कार्यों में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं त्वरितता सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से यह परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना के माध्यम से वर्तमान में 67 विभाग/एजेन्सियों द्वारा

कार्यादेश जारी किये जा रहे हैं तथा अब तक लगभग रूपये 36 हजार करोड की राशि के लगभग 20,000 टेण्डर जारी किये जा चुके है।

(v) प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन

राज्य शासन के विभिन्न विभागों की गतिविधियों, चाहे वे लोक सेवाऐं हों अथवा नियमित प्रशासनिक कार्य, की गुणवत्ता को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर एवं विकसित बनाये जाने की दिशा में विभाग निरन्तर प्रयासरत है। मैप–आई.टी. द्वारा नियमित रूप से ई–गवर्नेन्स के क्षेत्र में नियमित रूप से विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस वर्ष अभी तक 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 244 प्रशिक्षणार्थियों को ई–गवर्नेन्स क्रियान्वयन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त नवनियुक्त जिला ई–गवर्नेंस मैनेजर्स तथा सहायक ई–गवर्नेंस मैनेजर्स के प्रशिक्षण का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पुरस्कारों का वितरण

सूचना प्रौद्योगिकी को बढावा देने के लिये राज्य शासन द्वारा इस क्षेत्र में उत्तम कार्यो के लिये पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग/कार्यालय/संस्था को 10 जुलाई, 2012 को निम्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किये गये है:–

- *The Best IT for Masses Project Implemented by State Government Department/Agency*
- *The Best Application Software Developed and Implemented in Madhya Pradesh.*
- *The Best Innovative use of Technology in Government Functioning in Madhya Pradesh*
- *The Best use of GIS in bringing e Governance solutions in Madhya Pradesh*
- *The Best use of Mobile Technology : m-Governance in Madhya Pradesh*
- *The Best District/Department/Agency to perform GPR to improve Service Delivery System*
- *Special Jury Award*

1.4 विभाग के दायित्व

विभाग के दायित्व मुख्यतः निम्नानुसार है :–

(i) सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएँ सम्मिलित हैं।

(ii) समस्त स्तरों पर नागरिक सेवाओं के सुधार के लिए ई–गवर्नेस का संवर्धन।

(iii) राज्य सरकार के समस्त विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों में सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें कम्प्यूटरीकरण सम्मिलित है, के उपयोग का संवर्धन।

(iv) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा नागरिक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की परियोजनाओं के संबंध में सहायता तथा समन्वय।

(v) जनता के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना तथा बोधगम्य बनाना।

(vi) राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति तथा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समन्वय।

(vii) सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलनों का आयोजन।

(viii) कम्प्यूटरों के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा हार्डवेयर पार्क से संबंधित औद्योगिक केन्द्रों, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इलैक्ट्रॉनिक्स से संबंधित संचार उपकरणों की स्थापना में अभिवृद्धि तथा सहायता और ऐसे प्रयासों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन।

(ix) ग्रामीण इंटरनेट तथा अन्य इंटरनेट आधारित सूचना प्रणाली, जिसमें विभिन्न सेवाओं के लिए सूचना बूथों (कियोस्क) तथा आभासी कार्यालयों की स्थापना सम्मिलित है, का प्रोन्नयन।

(x) विभिन्न विभागों के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों तथा उपयोजनाओं के संबंध में परामर्श।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

विभाग भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं म.प्र. सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 तथा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति–2012 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है। विभाग के अधीन वर्तमान में संसदीय कार्य एवं विधि विषयक कार्य नहीं किए गए हैं। विभाग के अधीन कोई न्यायालयीन निर्णय के प्रकरण

लंबित नहीं है। विभाग के अधीन कोई संचालनालय/जिला कार्यालय कार्यरत् नहीं होने से विभागीय जाँच पदोन्नति, नियुक्ति, आदि की जानकारी निरंक है।

1.6 सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गव्हर्नेन्स प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता बनती जा रही है। शासन के विभिन्न अंगों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने हेतु विभाग उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। विभाग का प्रयास रहा है कि राज्य शासन के विभिन्न अंगों को आधारभूत अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाये। इस दिशा में विभाग ने ठोस प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, स्टेट डाटा सेन्टर जैसी अधोसंरचनाऐं अतिशीघ्र विभिन्न विभागों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दी जायेंगी।

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु विभाग द्वारा कई कदम उठाए गये हैं। विभाग द्वारा निवेश आकर्षित करने हेतु हैदराबाद, बंगलूरू, इन्दौर तथा दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स इन्टरेक्टिव सेशन्स का आयोजन किया गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में निवेश का अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। वर्ष 2012 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मिट मीट में विभाग द्वारा 47 सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के साथ लगभग रूपये 3000.00 करोड़ के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये।

1.7 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

विभाग के अधीन कोई संचालनालय नहीं है तथा विभाग अन्य विभागों को परामर्श के माध्यम से कार्य करता है। विभाग आवश्यकता पड़ने पर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बारे में निर्देश जारी करता है।

भाग–दो

2.1 – 2.2 : बजट विहंगावलोकन एवं बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)

विभाग को वर्ष 2012–13 में द्वितीय अनुपूरक अनुमान सहित रूपये 6298.84 लाख का बजट प्राप्त हुआ है जो निम्नानुसार हैः–

बजट प्रावधान वर्ष 2012–2013 द्वितीय अनुपूरक अनुमान सहित

(आंकडे लाख में)

योजना का नाम	आयोजना राशि	माह दिसम्बर 2012 तक व्यय
5722- कॉल सेन्टर की स्थापना	250.00	180.00
6760-नई तकनीक हेतु मैपीट अथवा अन्य संस्थाओं को सहायता	500.00	300.00
6874-स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना	1058.00	471.00
8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य – परीक्षा प्रशिक्षण,	255.00	40.00
8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य – सेमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन	170.00	50.00
8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य – 44– राज सहायता,	240.00	30.00
5125- मैप–आईटी में जीआईएस लैब की स्थापना	100.00	75.00
0701-केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाऐं : 6873– राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान	434.17	00
5818–डाटा सेन्टर बिल्डिंग का निर्माण, 33–अनुरक्षण कार्य, 002–मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण	1041.66	00
5818–डाटा सेन्टर बिल्डिंग का निर्माण 64–वृहद निर्माण कार्य, 002–उप वृहद निर्माण कार्य	0.01	00
0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6615–प्रदेश में आईआईआईटी की स्थापना	250.00	0
7062–प्रदेश में आईटी पार्क की स्थापना,45–001–पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	2000.00	0
योग मांग संख्या –69	**6298.84**	**1146.00**

भाग–तीन

3.1 राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1.1 राज्य योजनाएँ

(i) जी.आई.एस. लैब की स्थापना

सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत एक पूर्ण जी.आई.एस. लैब की स्थापना की जा रही है। जिसमें मैप सर्वर, वर्क स्टेशन, स्केनर, प्लॉटर एवं मैप डाटा उपलब्ध रहेगा। उपरोक्त सेन्टर प्रारम्भ होने पर प्रदेश के लिये प्राकृतिक एवं भौतिक अद्योसंरचना संबंधी संसाधन प्रबंध प्रणाली विकसित हो जायेगी। योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है ताकि इसका लाभ सम्पूर्ण राज्य को प्राप्त हो सके।

(ii) नई तकनीक हेतु संस्थाओं को सहायता–

सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे नित नई तकनीकों के प्रयोगों के पोषण हेतु शासकीय विभाग एवं संस्थाओं को इस योजना मद से सहायता दी जाती है। विभाग के पास विभिन्न विभागों/जिला कार्यालयों जैसेः– महिला एवं बाल विकास विभाग (लाड़ली लक्ष्मी योजना), लोक सेवा प्रबंधन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग (समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम), किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, भोपाल, मण्डीबोर्ड, आदि के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने, लोकल एरिया नेटवर्क विकसित करने, प्रशिक्षण प्रदान करने आदि के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(iii) कॉल सेन्टर की स्थापना–

भोपाल में राज्य के लिए कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है। इस कॉल सेन्टर में नागरिक दूरभाष क्रमांक 155343 लगाकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं शिकायत दर्ज करा सकते है। कॉल सेन्टर पर 21 विभागों/कार्यालयों की 325 सेवाओं के लिए अब तक 34.10 लाख कॉल्स प्राप्त हुये हैं। इनमें से 95 प्रतिशत से अधिक निराकृत किये जा चुके हैं। राज्य शासन द्वारा अब कॉल सेंटर परियोजना के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग के को नोडल विभाग बनाया गया है।

3.1.2 **केन्द्र प्रवर्तित योजना**

विभाग में निम्नलिखित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं संचालित हैः–

(i) **राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान,**

नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान के तहत प्रदेश का ई–गवर्नेन्स रोड मैप एवं ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार किया जाकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। ब्ल्यू प्रिन्ट पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति के बाद रोड मैप के अनुसार चयनित विभागों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य प्रांरभ किया जायेगा। परियोजना अन्तर्गत भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार मिशन मोड परियोजनाओं को एकीकृत कर कम्प्यूटराईजेशन के लिए परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है (Central MMP, State MMP & Integrated MMP)। भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को अपनी आवश्यकता के अनुसार पाँच अन्य परियोजनाओं का चयन करने की अनुमति प्रदान की गई है। परियोजना के तहत वाणिज्यिक कर, स्वास्थ्य, वन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उद्यानिकी, जेल, पुलिस तथा कोष एवं लेखा आदि विभागों को कम्प्यूटराईजेशन के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है।

(ii) **स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना,**

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 360 Points of Presence (POP) केन्द्रों की स्थापना की जाना है। परियोजना के अंतर्गत ब्लाक जिले से, जिले संभाग से तथा संभाग से भोपाल हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ जाएंगे। परियोजना के पॉच वर्ष तक संचालन हेतु उपयुक्त भागीदार मेसर्स ट्यूलिप आई.टी. सर्विस का चयन किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 360 Points of Presence (POP) केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। अब तक 332 पॉप केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। नेटवर्क आपरेटिंग सेन्टर क्रियाशील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 33 विभागों के लगभग 1300 कार्यालयों को Horizontal Connectivity प्रदान की जा चुकी है, जिनमें वाणिज्यिक कर विभाग, कोषालय, आबकारी कार्यालय, परिवहन विभाग, लोक सेवा केन्द्र, वन, नगर निगम भोपाल के 87 स्थान, उच्च न्यायालय एवं 50 जिला न्यायालय, ऊर्जा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व, महिला एवं बाल विकास तथा मछली पालन एवं मछुआ विकास प्रमुख हैं।

इस नेटवर्क के माध्यम से ब्लाक से जिले (स्पीड–2Mbps), जिले से संभाग (स्पीड–10Mbps) तथा संभाग से राज्य (स्पीड–34Mbps) हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ गये हैं। इसके अतिरिक्त इस नेटवर्क से सभी 400 लोक सेवा केन्द्रों एवं 5000 से अधिक पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों को जोड़ा जा रहा है। स्वॉन को निकनेट (NICNET) से भी जोड़ा जा चुका है, जिससे एन.आई.सी. की समस्त एप्लीकेशंस अब स्वॉन नेटवर्क पर उपलब्ध हो चुकी हैं। SWAN पर Internet सुविधा भी प्रदान की जा रही है। वर्तमान में उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों एवं विभागों के नेटवर्क पूर्णतः SWAN पर कार्य कर रहे हैं और यही कारण है कि नेटवर्क की विश्वसनीयता, अबाधितता, उच्च अपटाईम एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदाय किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है ताकि नेटवर्क के परिचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी की समअतिरिक्त/वैकल्पिक व्यवस्था (Redundancy) निर्मित की जा रही है।

(iii) कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना–

भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं म.प्र. शासन की संयुक्त भागीदारी से सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को आम नागरिकों तक पहुॅचाने के लिए प्रदेश में 9232 कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना की जा रही है।

परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जारी निविदा के माध्यम से 5 संस्थाओं का चयन किया गया है। ये संस्थाऐं हैं। AISECT (चंबल, सागर,रीवा एवं होशंगाबाद संभाग), CMS Computers (ग्वालियर एवं भोपाल संभाग), NICT (इन्दौर एवं उज्जैन संभाग), Reliance Communications (जबलपुर संभाग)। चयनित संस्थाओं के साथ अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। अब तक लगभग 9299 सेन्टरों की स्थापना हो चुकी है। इन सेंटरों द्वारा किसानों के पंजीयन का कार्य भी किया जा रहा है।

(iv) स्टेट डाटा सेन्टर

भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना अन्तर्गत भोपाल में स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना की गई है। स्टेट डाटा सेन्टर ने दिनांक 12.12.2012 से कार्य करना शुरू कर दिया है। योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी मध्यप्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम है। परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा रूपये 55.75 करोड स्वीकृत किये गये है जिसमें पूंजीगत व्यय हेतु

रूपये 14.56 करोड एवं अगले पांच वर्ष में योजना के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु रूपये 41.19 करोड का प्रावधान शामिल है। इस सेन्टर के माध्यम से एनईजीपी के तहत सरकार की सेवाओं को संघटित करने, दक्ष इलोक्ट्रोनिक सर्विस प्रदान करने के लिए आवेदनों/अधोसंरचना को जुटाया जायेगा। परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जावेगी :–

- डाटा सेन्टर से स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी
- डाटा सेन्टर से डिजास्टर रिकवरी सेन्टर की कनेक्टिविटी

(v) ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना

यह परियोजना भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 5 जिलों (इन्दौर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी एवं सागर) में आम नागरिकों को नागरिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग द्वारा पारदर्शी एवं त्वरित लोक सेवाऐं प्रदान करने हेतु पायलट आधार पर प्रारम्भ किया गया था। प्रदेश में इस परियोजना के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्मित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर उक्त पांचों जिलों में स्थापित 38 लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से 8 सेवाऐं प्रदान करने का कार्य 27 जुलाई, 2012 से सफलतापूर्वक प्रारम्भ कर दिया गया है। परियोजना का संचालन लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से नये सिरे से प्रारम्भ किये जाने तथा इस कार्य में लोक सेवा केन्द्र संचालकों एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत अधिसूचित पदाभिहित अधिकारियों को अधिकृत किये जाने के कारण इन पांचों जिलों में सामान्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, डिजिटल हस्ताक्षर तथा नेटवर्क /कनेक्टिविटी के लिए नये सिरे से कार्यवाही की गई। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अब इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

(vi) स्टेट पोर्टल एवं स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे (SSDG)

राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना के अंतर्गत नागरिकों को दूरस्थ अंचलों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से त्वरित, पारदर्शी एवं सुविधाजनक रूप से सेवाऐं प्रदान करने के उद्धेश्य से भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से स्टेट पोर्टल एवं स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे (SSDG) की स्थापना की जा रही है। यह मूलतः आई.टी. अधोसंरचना के रूप में स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे की स्थापना एवं स्टेट पोर्टल के निर्माण से संबंधित मिशन मोड परियोजना है। परियोजना पीपीपी मोड पर संचालित की जा रही है जिसके लिए टीसीएस का चयन निजी भागीदार के रूप में किया गया है। टीसीएस के द्वारा परियोजना के वास्तविक संचालन प्रारम्भ से

आगामी 3 वर्ष तक सपोर्ट प्रदान किया जायेगा। परियोजना की कुल लागत 10.84 करोड़ रूपये है जो भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से निम्न प्रमुख गतिविधियॉ संचालित की जाना है :–

1. प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक फ्रन्ट एण्ड के रूप में स्टेट पोर्टल की स्थापना एवं उसे राष्ट्रीय पोर्टल के साथ समेकित करना जिससे नागरिकों को प्रदेश के समस्त विभागों एवं योजनाओं आदि की जानकारी तथा विभिन्न सेवाओं के संबंध में जानकारी एक ही स्थान पर अत्यंत सहज एवं सरल रूप में प्राप्त हो सके। पोर्टल हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विकसित किया जायेगा।
2. परियोजना के अंतर्गत चयनित विभागों की चयनित सेवाओं के लिए e-Forms का निर्माण किया जा रहा है जो स्टेट पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। इन e-Forms को नागरिक ऑनलाईन/नागरिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से भर कर submit कर सकेगें। इस प्रकार Submit किये गये e-Forms स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे के माध्यम से संबंधित विभाग को ऑनलाईन प्राप्त हो सकेगें। विभाग द्वारा उनका निराकरण कर वस्तुस्थिति की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
3. परियोजना के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों की वेबसाईट्स को मानक स्वरूप में विकसित करने का कार्य भी किया जायेगा। यह सभी वेबसाईट्स भारत सरकार एवं Cert-in की गाईड लाईन के अनुरूप तथा IPv6 compliant होंगी।
4. परियोजना का एक प्रमुख कार्य SSDG एवं स्टेट पोर्टल को समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना, यूआईडी एवं एमपीऑनलाईन परियोजनाओं के साथ भी Integrate करना है।

<u>परियोजना की प्रगति :</u>

1. परियोजना के अंतर्गत e-Forms के विकास के लिए जिन 6 विभागों एवं उनकी 41 सेवाओं का चयन किया गया है वे हैं :– उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन एवं मछुआ विकास, महिला एवं बाल विकास, जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। इन सभी विभागों से चरणबद्ध चर्चाओं के बाद सहमति प्राप्त कर सभी 41 सेवाओं के लिए e-Forms विकसित कर लिये गये हैं।
2. परियोजना के अंतर्गत निम्न 13 विभागों का चयन किया गया है जिनकी वेबसाईट्स को भारत सरकार एवं Cert-in की गाईड लाईन के अनुरूप तथा IPv6 compliant रूप में एक ही Look-n-Feel के साथ विकसित किया जायेगा :–
   I. वित्त विभाग।
   II. सामान्य प्रशासन विभाग।

III. विधि एवं विधायी कार्य विभाग।
IV. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।
V. मत्स्य पालन एवं मछुआ विकास विभाग।
VI. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।
VII. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
VIII. संस्कृति विभाग।
IX. महिला एवं बाल विकास विभाग।
X. खनिज साधन विभाग।
XI. राजस्व विभाग।
XII. श्रम विभाग।
XIII. सहकारिता विभाग।

3.1.3 विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं

विभाग में विश्व बैक की सहायता से कोई योजना संचालित नहीं है ।

3.1.4 विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं

विभाग विदेशी सहायता से कोई परियोजना नहीं चला रहा है ।

3.2 वर्ष के दौरान विभाग की उपलब्धियॉ

3.2.1 ई–टेण्डरिंग :–

निर्माण विभागों से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों के प्रकाशन विक्रय एवं खोलने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक टेण्डरिंग एक अत्यंत विश्वसनीय तकनीक है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता, सुविधा एवं त्वरितता जैसी विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिपरिषद निर्णय दिनांक 22 अगस्त, 2006 द्वारा ई–टेण्डरिंग व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना के संचालन के लिए नोडल एजेन्सी मैप–आई.टी. द्वारा निविदा आमंत्रित कर मेसर्स विप्रो नेक्स्टेण्डर कन्सोर्शियम का चयन निजी भागीदार के रूप में किया गया। ई–टेण्डरिंग व्यवस्था 25 मई, 2007 से सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं नर्मदाघाटी विकास विभाग में लागू की गई।

परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं नवीन आरएफपी का निर्माण :
वर्तमान में शासन के 73 विभाग/कार्यालयों में परियोजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। **अभी तक** लगभग 36 हजार करोड़ रूपये की लागत के लगभग 20 हजार टेण्डर उक्त पोर्टल के माध्यम से जारी किये जा चुके हैं।

ई–टेन्डरिंग उपयोगकर्त्ताओं की संख्या लगभग 10,000 है। ई–टेण्डरिंग परियोजना के निजी भागीदार के साथ वर्तमान अनुबंध की समाप्ति के फलस्वरूप पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के द्वारा नये भागीदार के रूप में टी.सी.एस.–एन्टारेस सिस्टम्स लि. का चयन कर लिया गया है। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अब इस परियोजना का क्रियान्वयन मैप–आई.टी. के स्थान पर एमपीएसईडीसी द्वारा किया जा रहा है।

3.2.2 एमपी ऑन लाईन पोर्टल का विकास :–

राज्य शासन द्वारा सुदूर क्षेत्रों में नागरिकों को कहीं भी कभी भी (Any Time Anywhere) शासकीय सेवाऐं प्रदान करने के लिए mponline नामक पोर्टल www.mponline.gov.in विकसित किया गया है। एमपीऑनलाईन मध्यप्रदेश शासन एवं टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेस का संयुक्त उपक्रम है जिसमें मध्यप्रदेश शासन की एम.पी.एस.ई.डी.सी. के माध्यम से 11 प्रतिशत की भागीदारी है। एमपीऑनलाईन द्वारा मुख्यतः शैक्षणिक, भर्ती संबंधी, बी–टू–सी एवं काउंसिलिंग संबंधी लगभग 225 सेवाऐं 3000 से अधिक एमपीऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। एमपीऑन लाईन देश के सर्वाधिक सफल लोक सेवा प्रदाय मॉडलों में से एक है।

3.2.3 प्रदेश में इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी एसईजेड की स्थापना :–

1. भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर को आई.टी. हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 जारी की गई है। इंदौर में टीसीएस, इंफोसिस एवं इम्पेटस कम्पनियों को आई.टी.एसईजेड के विकास हेतु भूमि आवंटित की गई है। ग्वालियर में आई.टी. पार्क की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भोपाल के बड़वई एवं इंदौर के सिंहासा में आई. टी. पार्क के निर्माण के लिये कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

3.2.4 ई–गवर्नेन्स मैनेजर्स की नियुक्तियॉ :

जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं जिलों में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने के उद्धेश्य से जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी के अधीन जिला स्तर पर 50 जिला ई–गवर्नेन्स मैनेजर्स एवं 50 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स तथा विकासखण्ड स्तर पर 320 सहायक ई–गवर्नेन्स मैनेजर्स इस प्रकार कुल 420 पदों का सृजन किया गया। इन पदों पर ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियॉ की जा चुकी हैं। इन सभी मैनेजर्स के प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

भाग–चार

4.1 सामान्य प्रशासनिक विषय

विभाग के अधीन कोई विभागाध्यक्ष तथा जिला कार्यालय नहीं है। प्रशासनिक विषय निरन्क हैं।

भाग–पॉच

5.1 अभिनव योजनाऐं

विभाग द्वारा निम्नानुसार अभिनव योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है :–

1. **वर्चुअल क्लास रूम परियोजना** – इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 313 विकासखण्ड मुख्यालयों पर चिन्हांकित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 100 शासकीय महाविद्यालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजना का पायलट फरवरी 2013 से प्रदेश के 15 चिन्हित स्थानों पर प्रारंभ किया जा रहा है।

2. **स्टेट रेसिडेंट डेटा हब परियोजना**– इस परियोजना के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के केन्द्रीय डेटाबेस से म.प्र. के नागरिकों का संपूर्ण डेटा प्राप्त कर स्टेट डेटा सेंटर में पृथक रिपाजिटरी में विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों के उपयोग हेतु रखा जावेगा। इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 10 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

3. **जीआईएस लैब परियोजना** – प्रदेश में जीआईएस संबंधी गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं समन्वयन के लिये एनआईसी के सहयोग से यह अभिनव योजना प्रारंभ की गई है।

4. **एमपीकोड परियोजना** – म.प्र. के विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों की एक स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये इस परियोजना अंतर्गत एनआईसी के सहयोग से पोर्टल विकास का कार्य किया जा रहा है।

5. फिनिशिंग स्कूल प्रारम्भ करना – प्रदेश के युवा इंजीनियरों में आईटी स्किलगैप को समाप्त करने के उद्देश्य से महू में फिनिशिंग स्कूल की स्थापना की गई है। यहां युवाओं को स्किल गैप प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की योजना है।

भाग–छः

6.1 विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

स्थाई प्रकाशन

- मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2006
- मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति–2012
- मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी (नागरिक सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदाय तथा सेवा प्रदाता की नियुक्ति का विनियमन) नियम–2011.

वार्षिक/त्रैमासिक प्रकाशन

- आई.टी. न्यूज लेटर
- आई.टी. कम्पेन्डियम (Successful e-Governance Projects in Madhya Pradesh)

भाग–सात

7.1 सारांश

विभाग चार प्रमुख उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है :– 1. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना 2. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना का विकास करना 3. प्रदेश में सुशासन की प्रभावी पहल के रूप में ई–गवर्नेंस एवं एम–गवर्नेन्स को सभी विभागों एवं कार्यालयों में लागू करना तथा 4. शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना। विभाग शासन की मंशा एवं विभागीय उद्देश्यों, नीतियों के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सफल रहा है।

==========

प्रपत्र–क

1. मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
टर्न ओवर आय	459.10	432.18	628.03	816.90	793.28	855.70	1060.73
शुद्ध लाभ/हानि	2.76	–1634.18	26.21	119.70	63.52	90.46	61.99
कैश लाभ/हानि	30.38	28.81	161.77	151.98	165.34	185.36	115.67
कुल पूंजी	2191.25	2191.25	2191.25	2191.25	2191.25	2191.25	2191.25
संचय एवं आधिक्य	1748.77	114.64	140.90	21.25	84.83	175.34	257.74
नेट वर्थ	**6433.18**	**2305.89**	**2332.15**	**2212.50**	**2276.07**	**2366.59**	**2448.98**

प्रपत्र–ख

2. मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (MAP_IT)

वर्ष	प्रत्यक्ष राज सहायता (राशि रूपये लाख में)
2002–2003	30.00
2003–2004	36.00
2004–2005	10.42
2005–2006	25.00
2006–2007	20.00
2007–2008	29.57
2008–2009	26.12
2009–2010	30.87
2010–2011	31.25
2011-2012	63.95
2012-2013	240.00